आधार

वर्ष 3, अंक 1, 2006

CUTS International

आधारभूत सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु त्रैमासिक पत्रिका

विद्युत सुधारों में उपभोक्ता की भूमिका एवं जन सहभागिता

'कट्स' - कार्ट एवं जर्मन संस्थान 'फ्रेडरिच इबर्ट स्टिफ्टंग' (एफ.ई.एस.) द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे राजस्थान में विद्युत सुधारों में उपभोक्ता की भूमिका एवं जन सहभागिता विषय पर दूसरे चरण की परियोजना जिसका शुभारम्भ मई, 2005 में आरम्भिक बैठक से हुआ था, के अन्तर्गत जनवरी से मार्च, 2006 के दौरान तीन वृत्त स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि दिनांक 27 जनवरी, 2006 को अजमेर विद्युत वितरण कंपनी के अन्तर्गत झुन्झुनू में; दिनांक 10 फरवरी, 2006 को जोधपुर विद्युत वितरण कंपनी के अन्तर्गत बाड़मेर में और दिनांक 21 मार्च, 2006 को अजमेर विद्युत वितरण कंपनी के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ में आयोजित किए गए।

जनप्रतिनिधि श्रीमती सुनीता देवी कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए।

झुन्झुनू में जिले की विभिन्न पंचायत समितियों के 49 संभागियों ने कार्यशाला में भाग लिया, इसी प्रकार बाड़मेर में 55 तथा चित्तौड़गढ़ में 75 संभागियों ने कार्यशाला में भाग लेकर अपनी सहभागिता प्रदान की। झुन्झुनू जिले में अधिशासी अभियंता एस.एम. बिल्खिवाल एवं सहायक अभियंता गोविन्द शर्मा ने संभागियों को तकनीकी जानकारी दी, वहीं श्रीमती सुनीता देवी, जन प्रतिनिधि तथा हरीप्रसाद योगी, कट्स कार्यकर्ता ने गैर-तकनीकी विषयों पर संभागियों को सम्बोधित किया।

बाड़मेर में अधिशासी अभियंता ओ.पी. चांडक तकनीकी जानकारी देने के लिए उपस्थित थे, वहीं नथमल परमार, सहायक जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, बाड़मेर ने गैर-तकनीकी विषयों पर जानकारी प्रदान की।

चित्तौड़गढ़ में अधीक्षण अभियंता बी.एल. महेश्वरी ने तकनीकी विषयों पर जानकारी दी तथा गंगाधर सोलंकी तथा हरीप्रसाद योगी, कट्स कार्यकर्ता ने पैरवी व नियमन आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की।

जहां झुन्झुनू में राजेन्द्र सेन (सारथी संस्थान) के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं बाड़मेर में चेलाराम मकवाना (ग्रामीण मार्गदर्शन समिति) तथा चित्तौड़गढ़ में 'कट्स' मानव विकास केन्द्र के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपरोक्त कार्यशालाओं में नियामक आयोग की कार्यप्रणाली, नियमन, विद्युत दरों की समीक्षा, पैरवी, उपभोक्ता व उपभोक्ता संस्थाओं की भूमिका तथा नागरिक अधिकार पत्र आदि विषयों के अतिरिक्त विद्युत सुधार समितियों को गतिशील बनाना, विद्युत चोरी एवं विद्युत छीजत रोकने में सरकार की सहायता करने संबंधी सुझावों पर चर्चा की गई। इससे कई महत्वपूर्ण सुझाव भी निकल कर सामने आए।

पूर्व में आयोजित वृत्त स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा

स्थान	दिनांक	मुख्य वक्ता	सह आयोजक/समन्वयक
सवाई माधोपुर	20.06.05	आर.के. जैन, अधीक्षण अभियंता	कन्ज्यूमर लीगल हेल्प सोसायटी/ हरीप्रसाद योगी
कोटा	16.07.05	सी.पी. विजयवर्गीय, अधीक्षण अभियंता	जिला कोटा उपभोक्ता संरक्षण समिति/ फ़ज़र मोहम्मद
अलवर	23.07.05	एस.सी. मित्तल, अधीक्षण एवं राजेश तिवाड़ी, सहायक अभियंता	शुभम संस्थान/श्रीमती सुशीला देवी
फागी (जयपुर)	13.08.05	के.सी. जैन, अधीक्षण एवं पी.के. माथुर, सहायक अभियंता	अमन विकास संस्थान/सुरेश सैनी
जालौर	10.09.05	आर.एस. चौधरी, मुख्य अभियंता	संकल्प संस्थान/महेन्द्र कुमार ओझा
जोधपुर	15.10.05	आर.एस. चौधरी व एच.एस. देवड़ा, मुख्य अभियंता	उपभोक्ता मागदर्शन समिति/ लियाकत अली
चूरू	9.11.05	ओ.पी. गौड़, अधिशासी एवं आर.सी. खंडेलवाल, सहायक अभियंता	सारथी संस्थान/राजेन्द्र सेन

...✍ पहचानना होगा पानी का मूल्य

गर्मी का मौसम और पानी की किल्लत। राजस्थान में पूरे देश का एक प्रतिशत ही पेयजल उपलब्ध है, जो पर्याप्त नहीं है। भूजल का दोहन बढ़ता जा रहा है। राज्य में 94 प्रतिशत पेयजल व्यवस्था और 70 प्रतिशत कृषि क्षेत्र पूरी तरह भूजल पर निर्भर है। शहरों में निरर्थक भूजल का दोहन और गांवों में विद्युतिकरण से कृषि क्षेत्र में भूजल का तीव्र गति से दोहन बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप राज्य के 237 खण्डों में से केवल 32 खण्ड ही ऐसे बचे हैं, जिनमें भूजल की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। राज्य का 70 प्रतिशत क्षेत्र डार्क जोन में आ चुका है। वर्षा का अनुपात भी गिरा है और पड़ोसी राज्य भी पानी देने में आनाकानी कर रहे हैं। अब हमारे पास पानी का संरक्षण और पुर्नभरण के साथ-साथ पानी के अपव्यय को रोकने के ही विकल्प बचे हैं। यह कार्य सिर्फ सरकार के बलबूते पर नहीं हो सकता। इन सभी में जनता की सीधी भागीदारी आवश्यक है।

इस अंक में...

हवा से बनेगी 500 मेगावाट बिजली . 2
कैसे हो पीने के पानी का समाधान ... 3
बरसाती पानी - बचाना जरूरी 4
लो कर लो बात एक रुपए में 5
जयपुर शहर में बनेंगे फ्लाईओवर 6
ट्रेफिक प्लान सुधार पर पूरी नजर 7

प्रदीप मेहता केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की सलाहकार समिति में

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) के महामंत्री प्रदीप एस. महता को केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। श्री महता विद्युत नीति, गुणवत्ता, सतत् आपूर्ति एवं अनुज्ञा-पत्र धारियों द्वारा सेवा प्रदान करने, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सेवा उपलब्ध कराने आदि के बारे में आयोग को सलाह देंगे।

आयोग के अध्यक्ष अशोक बसु ने बताया कि केन्द्रीय सलाहकार समिति की भूमिका, बढ़ते विद्युत बाजार में प्रतिस्पर्धा, कार्य दक्षता एवं मितव्यता को प्रोत्साहन देने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, निवेश बढ़ाने एवं मांग तथा आपूर्ति के अंतर को कम करने हेतु संस्थागत बाधाओं को हटाने के लिए सरकार को सलाह देने तथा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखने की है।

विद्युत उत्पादन में नया कीर्तिमान

राज्य के कोटा और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पॉवर स्टेशनों ने वर्ष 2005 में विद्युत उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कोटा सुपर पॉवर स्टेशन ने 9269.62 मिलियन यूनिट तथा सूरतगढ़ सुपर पॉवर स्टेशन ने 9661.46 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया।

वर्ष 2004 में कोटा थर्मल ने 6978.14 तथा सूरतगढ़ थर्मल ने 9511.24 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया था। इस साल दोनों थर्मलों ने क्रमशः90.34 तथा 88.96 फीसदी प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया, जबकि वर्ष 2004 में यह 85.28 और 86.62 था।

(रा.स्टे., 04.01.06 एवं न.नु., 08.01.06)

अमानत राशि पर मिलेगा ब्याज

राज्य की तीनों बिजली वितरण कंपनियां अपने सभी उपभोक्ताओं को उनकी अमानत राशि पर हर साल ब्याज देंगी। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गत माह विद्युत कम्पनियों को अमानत राशि पर ब्याज देने के निर्देश जारी किए थे।

आयोग भी हर महीने ब्याज देने की कार्रवाई पर निगरानी रखेगा। यह राशि उपभोक्ताओं के बिलों में समाहित की जाएगी। जमा अमानत राशि में अन्तर पाए जाने पर उपभोक्ता एईएन कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

(रा.प., 15.02.06 एवं दै.भा., 30.03.06)

बिजली संकट दूर करने में जुटी सरकार

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि बिजली संकट के दौर से गुजर रहे प्रदेश में विद्युत हालत में सुधार के लिए सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य में बिजली का संकट काफी हद तक दूर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश कर रही है। उनकी सरकार का प्रयास है कि हर घर में बिजली पहुंचे।

यह योजना आगामी तीन साल में क्रियान्वित होगी। योजना में मुख्य जोर बिजली की छीजत और चोरी रोकने पर रहेगा। यदि हम छीजत को 8 प्रतिशत भी कम करने में सफल रहे तो किसानों के लिए बिजली की कमी नहीं रहेगी।

राज्य में 1125 फीडर ऐसे पाए गए हैं जिनमें बिजली छीजत औसतन 62 प्रतिशत तक है। इसमें 40 फीसदी से ज्यादा चोरी हो रही है । मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों के फीडर सुधार की धीमी गति पर अपनी नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसके लिए लताड़ा है।

(रा.प., 10.01.06 एवं दै.भा., 12.01.06)

शहर में बनेंगे चार नए विद्युत केन्द्र

जयपुर शहर की बिजली सप्लाई में सुधार लाने और उच्च गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 220 केवी का एक और 132 केवी के तीन नए बिजली सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इससे बढ़ती बिजली की मांग भी पूरी हो सकेगी।

यह जानकारी बिजली वितरण कंपनियों के अध्यक्ष श्रीमत पांडे ने देते हुए बताया कि शहर के बिजली तंत्र को अधिक मजबूत करने के लिए विश्वकर्मा,झोटवाड़ा, जगतपुरा और इंदिरा बाजार में सब स्टेशनों की मंजूरी दी जा चुकी है। इस समय शहर में 220 केवी के तीन और 132 केवी के बारह सब स्टेशनों से बिजली की सप्लाई की जा रही है। *(दै.भा. एवं रा.प., 27.03.06)*

एक साल में होगा हर गांव रोशन

एक साल के बाद राज्य के हजारों गांवों को सुबह-शाम घरेलू बिजली नहीं आने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। गांवों को सिंगल फेस बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए करीब सात हजार फीडरों पर कृषि कनेक्शन व घरेलू आपूर्ति को अलग-अलग किया जाएगा। इसके लिए सिंगल फेस ट्रांसफारमर खरीदने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा बिजली चोरी व छीजत रोकने के लिए राज्य में फीडर सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें करीब आठ हजार फीडरों में तीन फेस व सिंगल फेस बिजली आपूर्ति को अलग-अलग करके ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे विद्युत चोरी और छीजत 15 से 20 फीसदी रोकी जा सके।

फीडर सुधार के बाद इससे जुड़े गांवों को 24 घण्टे सिंगल फेस बिजली दी जा सकेगी। राज्य की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे द्वारा इसके लिए बिजली कंपनियों को निर्देश दिए गए थे। इसके बाद अधिकारियों ने सभी ग्रामीण फीडरों पर सिंगल फेस ट्रांसफारमर लगाने की योजना बनाई है।

(दै.भा., 08.01.06 एवं रा.प., 02.03.06)

कोटा में सातवीं इकाई मंजूर

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट में 195 मेगावाट क्षमता की सातवीं इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय बारां जिले के छबड़ा के पास चौकी मोतीपुरा गांव में 500 मेगावाट के बिजलीघर को पहले ही अनुमति दे चुका है।

कोटा की सातवीं इकाई की लागत करीब 690 करोड़ रुपए है। यह इकाई मूल थर्मल पावर स्टेशन में लगेगी। इसके लिए अलग से आधारभूत ढांचे की जरूरत नहीं होगी। प्रस्तावित इकाई के निर्माण और उत्पादन शुरू होने के बाद इस पावर स्टेशन की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 1240 मेगावाट हो जाएगी। वर्तमान में यहां 110 मेगावाट की दो, 210 मेगावाट की तीन और 195 मेगावाट क्षमता की एक इकाई विद्युत उत्पादन कर रही हैं। *(रा.प., 10.02.06)*

हवा से बनेगी 500 मेगावाट बिजली

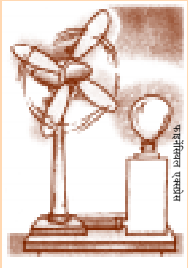

ऊर्जा मंत्री गजेन्द्र सिंह खिंवसर ने कहा है कि प्रदेश में अगले एक साल में पवन ऊर्जा से लगभग 500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर सहित अन्य जिलों में लगभग 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के संयत्र लगाए जा रहे हैं। सीकर जिले के हर्ष पर्वत पर भी निजी क्षेत्र में 16 पवन ऊर्जा उत्पादकों ने 20 संयंत्र लगाए हैं।

ऊर्जा सचिव यदुवेन्द्र माथुर ने भी इस बाबत मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में जानकारी दी कि राज्य में अब तक पवन ऊर्जा क्षेत्र में 1400 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इस साल पवन ऊर्जा से 250 व बायोमास से 30-35 मेगावाट बिजली उत्पादन की तैयारी है। इस पर राजे ने अधिकारियों को पवन, बायोगैस व बायोमास के माध्यम से अधिक से अधिक बिजली उत्पादन पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। (रा.प., 22.03.06 व दै.भा.एवं रा.प., 28.03.06)

सावधान-खतरे की घंटी बज चुकी है

जयपुर शहर और आसपास के गांवों में लगातार पानी का दोहन बढ़ रहा है। इससे धरती की कोख अब जवाब देने लगी है। धरती में पानी काफी नीचे जा चुका है। इससे पानी में लवणों की मात्रा बढ़ने से भूजल के जहरीले होने की खबरें मिल रही हैं। जयपुर जिले के करीब 80 फीसदी गांवों में आज पानी पीने लायक नहीं है। 771 गांव और 564 ढाणियां तो ऐसी हैं, जहां के पानी में फ्लोराइड, नाइट्रेट, लवण और लौह जैसे सभी तत्व हानिकारक मात्रा में मौजूद हैं। दूषित पानी के खतरों से अनजान लोग अनेक जानलेवा बीमारियों के शिकार बन रहे हैं।

हाल ही जल विज्ञानियों ने सभी तहसीलों के पांच हजार से ज्यादा गांवों और ढाणियों के भूजल का सर्वे किया तो यह तथ्य सामने आए। जयपुर और चौमूं में 66 फीसदी क्षेत्र का भूजल भारी लवणों वाला और रोगी बनाने वाला है। यही हाल दूदू, फागी और चाकसू के करीब सभी गांवों का है जहां पानी पीने लायक नहीं माना गया।

वरिष्ठ जल वैज्ञानिक डॉ.एस.एस.ढींढसा का कहना है कि जिले में जल के पुनर्भरण और पानी के संरक्षण के इंतजाम नहीं के बराबर हैं। दूसरी ओर भूजल का दोहन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से पानी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है।

(रा.प., 01.01.06)

कैसे हो पीने के पानी का समाधान?

देश के अनेक हिस्सों में बढ़ती पेयजल समस्या के समाधान पर चर्चा के लिए देशभर के करीब 500 जल विशेषज्ञ जयपुर स्थित बिड़ला सभागार में एकत्रित हुए। उनका कहना है कि राजस्थान में गिरते भूजल के काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी को जल गुणवत्ता के स्तर पर पूरी निगरानी रखनी होगी। इसके अलावा भूजल पुनर्भरण के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करने होंगे। एकमात्र यही एक ऐसा स्थाई समाधान है जो पेयजल दुष्प्रभाव को रोक सकता है।

विशेषज्ञों ने इंडियन वाटर वर्क्स ऐसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के तकनीकी सत्र में भूजल के गंभीर विषय 'जीवन के लिए जल' पर विस्तृत चर्चा की और अपने-अपने अनुभवों का आपस में आदान-प्रदान किया।

चर्चा में जल गुणवत्ता क्रियान्वयन और सतर्कता, व्यर्थ जल का उपचार, जल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों और कार्यनीति, सीवरेज उपचार जैसे अनेक विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। ये सुझाव पेयजल समस्या के स्थाई निराकरण के लिए कार्य योजना बनाने में उपयोगी साबित होंगे। इन सुझावों को भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को भी भिजवाया जाएगा।

(रा.प., 06.01.06 एवं दै.भा., 08.01.06)

वर्षाजल संरक्षण में केन्द्र करेगा सहयोग

केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राजस्थान सहित सभी राज्यों से जल योजना मांगी गई है। वर्षा जल संरक्षण सन्दर्भित इस योजना में केन्द्र सरकार राज्यों की पूरी मदद करेगी। यह जानकारी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद ने सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित संपादकों की छठी बैठक के दौरान राजस्थान पत्रिका की ओर से उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में दी ।

सम्मेलन में पत्रिका द्वारा मई-जून में चलाए गए 'अमृतम-जलम' अभियान की जानकारी दी गई थी और पूछा गया कि अकाल की बार-बार मार झेलने वाले इस राज्य में वर्षा जल संरक्षण के लिए प्राचीन बावड़ियों और तालाबों के पुनरुद्धार में क्या केन्द्र विशेष सहायता प्रदान करेगा ।

इस पर रघुवंश प्रसाद ने बताया कि राजस्थान से भी जल संरक्षण योजना मांगी गई है और केन्द्र उसमें राज्य सरकार को पूरी मदद देगा। राज्य सरकार ने वाटर प्लान तैयार कर केन्द्र को भिजवाने की पूरी तैयारी कर ली है।

(रा.प, 18.01.06 एवं हि.टा., 21.01.06)

जल संकट -पानी की हर बूंद बचाएं

पच्चीस साल पहले तक जयपुर शहर में जलस्तर 30 फुट पर था। भूजल के पुर्नभरण नहीं होने और अत्यधिक दोहन से आज पानी का स्तर 200 फुट तक पहुंच चुका है। यदि तीन साल तक बारिश नहीं होती है तो पेयजल का भारी संकट पैदा हो सकता है। इस भावी संकट से निपटने के लिए हर व्यक्ति को पहल करनी होगी।

आम लोगों को छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर रोजाना लाखों लीटर पानी बचाना होगा। यह तथ्य जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में जल अभियान कार्यशाला में उभर कर सामने आए। कार्यशाला का आयोजन संभाग स्तरीय जल अभियान समिति एवं राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास समितियों की ओर से किया गया था।

कार्यशाला में स्थानीय विकास समितियों के साथ संवाद के दौरान विशेषज्ञों ने पानी बचाने और भूजल पुर्नभरण के तौर-तरीकों को अपनाने पर बल दिया। समितियां अपने इलाके में व्यापक प्रचार प्रसार कर जल अभियान को सफल बनाने के लिए चेतना जागृत करेंगी। *(दै.भा.एवं रा.प., 17.02.06)*

जयपुर की प्यास बुझने की आस

लंबी अदालती लड़ाई से निजात मिलने से बनास नदी पर बने बीसलपुर बांध से जयपुर तक पीने का पानी लाने का रास्ता साफ हो गया है । बीसलपुर योजना के क्रियान्वयन का रास्ता साफ करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान अरबन इंफ्रास्टचर डवलपमेंट प्रोजेक्ट को इजाजत दे दी कि वह प्री-क्वालिफाइड बिड में चयनित चार आवेदकों की फाइनेंशियल बिड खोलकर सफल आवेदक का फैसला कर दे।

इस निर्णय से इस परियोजना में आर्थिक मदद देने वाले एशियाई विकास बैंक ने बारह करोड़ डॉलर मंजूर कर दिए हैं। जयपुर तक पानी लाने के लिए पाइप लाइन डालने का काम मार्च,2008 तक पूरा होने की आशा है। इसके बाद बीसलपुर से 36 करोड़ लीटर पानी रोजाना मिल सकेगा।

(रा.प., 07.02.06 एवं दै.भा., 23.03.06)

हर बस्ती में शुद्ध पेयजल

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की है कि भारत निर्माण योजना के तहत सरकार अगले चार साल में देश की हर बस्ती में शुद्ध पेयजल मुहैया कराएगी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल और सफाई कार्यक्रमों पर बल देते हुए कहा कि भारत निर्माण योजना के तहत हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम अगले चार साल के भीतर हर बस्ती में शुद्ध पेयजल मुहैया कराएं। इसके लिए यह भी जरूरी है कि जल आपूर्ति व्यवस्था को विकसित करने के लिए ठोस निवेश करें।

उन्होंने इसके लिए पांच सूत्री रणनीति को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने पर जोर दिया एवं जलापूर्ति की जिम्मेवारी को स्थानीय निकायों को सौंपने और स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता जताई।

(दै.भा. एवं रा.स्टे., 01.02.06)

पानी सरकार के लिए नहीं आमजन के लिए

इंडियन वाटर वर्क्स ऐसोसिएशन द्वारा जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राज्य के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रो. सांवरलाल जाट ने कहा कि राजस्थान का पानी सरकार के लिए नहीं, आमजन के लिए है।

उन्होंने जल के संरक्षण और पुनर्भरण में जन सहभागिता जुटाने के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता जताई। गिरते भूजल पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अधिक दोहन से पानी में खारेपन और फ्लोराइड जैसे तत्वों का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए हमें सतही जल पर आधारित जलप्रदाय योजनाएं बनाने पर ज्यादा जोर देना होगा।

उन्होंने कहा कि तकनीकी विशेषज्ञ इस बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दें, राज्य सरकार उनके ऐसे ठोस व उपयोगी सुझावों को लागू करने की पहल करेगी। इस अवसर पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्यमंत्री चुन्नीलाल धाकड़ ने कहा कि इंडियन वाटर वर्क्स ऐसोसिएशन 'आइवा' के सदस्य और उपस्थित विशेषज्ञ गांवों में उपलब्ध कम पानी से होने वाली फसलों की कार्य योजना तैयार करें। इससे न केवल युवा ग्रामीण काश्तकारों के रोजगार में वृद्धि होगी बल्कि शहरीकरण का दबाव भी कम हो सकेगा।

(रा.प. एवं दै.भा., 07.01.06)

महिलाओं की जल संरक्षण में भागीदारी

जल संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि वैज्ञानिकों का तकनीकी ज्ञान और महिलाओं की भागीदारी से जल संरक्षण के काम हाथ में लिए जाएं, तो हम रेगिस्तान को सरसब्ज कर सकते हैं। बरसात के पानी को संजो कर रखने और उसे साफ कर पीने योग्य बनाया जा सकता है।

इस बात को पिलानी के एक गांव रायला की महिलाओं ने सिद्ध कर दिखाया है। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नालॉजी एण्ड साइंस 'बिट्स' और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका 'राना' की संयुक्त परियोजना के तहत इन महिलाओं को जल संरक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया गया है।

पानी के संरक्षण के बड़े पैमाने पर चल रहे इस कार्य में झेड़ली ग्राम पंचायत के रायला गांव की महिलाएं बिना बिजली उपयोग के आधुनिक तकनीक के जरिए पानी से बैक्टीरिया तथा वायरस दूर कर उसे पीने योग्य बनाने में लगी हैं। इस तकनीक के काम में आने वाले फिल्टर केन्द्र सरकार के विज्ञान और तकनीकी विभाग ने उन्हें मुहैया कराया है। *(दै.भा., 17.01.06)*

शहर की जर्जर पाइप लाइनें बदलेंगी

जयपुर शहर की चारदीवारी क्षेत्र में 28.93 किलोमीटर लंबी पुरानी व जर्जर पानी की पाइप लाइनों को बदला जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ 93 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जलदाय विभाग के अनुसार चारदीवारी क्षेत्र की जर्जर लाइनों को बदलने के लिए 22 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना तैयार की गई थी।

वित्त समिति ने पहले चरण में मोतीडूंगरी रोड़ क्षेत्र व कमेलागली के आसपास की पुरानी लाइनों को बदलने के लिए 2.50 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। यह काम फरवरी माह से शुरू किया जाएगा।

द्वितीय चरण के तहत अब 4.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें रामगंज, कोठी कोलियान, घाटगेट, तोपखाना हजूरी, चार दरवाजा , सुभाषचौक और पुरानी बस्ती की 28.93 किलोमीटर लंबी पाइप लाइनें बदली जाएंगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 28.01.06)

पानी के मामले में राज्य को विशेष दर्जा मिले

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता विषय पर राज्यों के मंत्रियों की एक दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया। राज्य की ओर से पेयजल राज्य मंत्री चुन्नीलाल धाकड़ ने राज्य का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजस्थान में करीब दो-तिहाई बस्तियां आज भी ऐसी हैं जहां लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है।

केन्द्र सरकार को भारत निर्माण योजना के तहत प्रदेश की इस समस्या के समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा भी देना पड़े तो दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह सहित कई मंत्री और बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

धाकड़ का कहना था कि प्रदेश की भौगोलिक और संसाधनों की समस्या काफी पुरानी है। इससे मुक्ति पाने के लिए कुल 16 हजार 177 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। भारत निर्माण जैसा बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेने का मकसद यह होना चाहिए कि राज्यों की ऐसी मूलभूत समस्याओं का समाधान निकले। *(दै.भा.एवं रा.प. 01.02.06)*

पेयजल के लिए कवायद शुरू

पिछले कई सालों से पेयजल समस्या से जूझ रही जयपुर शहर की करीब 100 कॉलोनियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जलदाय विभाग ने स्थाई समाधान करने का दावा किया है। इन कॉलोनियों में दो माह बाद नए ट्यूबवैलों से पेयजल सप्लाई किया जा सकेगा। इससे इन कॉलोनियों के निवासियों को काफी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा गर्मियों में शहर में 300 लाख लीटर अधिक पानी सप्लाई किया जाएगा। इससे रोजाना 15 मिनट अतिरिक्त पानी शहरवासियों को मिल सकेगा। रामगढ़ बांध से भी रोजाना 80 लाख लीटर पानी लिया जाएगा।

जिले के ग्रामीण इलाकों में भी गर्मी के लिए जलदाय विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत कुछ क्षेत्रों में एक अप्रेल से 31 जुलाई तक रेल परिवहन द्वारा और कुछ क्षेत्रों में निजी खातेदारों के कुओं से पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा जिले के 910 गांवों व ढाणियों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।

इसके लिए जलदाय मंत्री ने हाल ही आगामी पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए। *(रा.प., 10 .02.06, 12.02.06 एवं 04.03.06)*

बरसाती पानी-बचाना जरूरी

शहरी क्षेत्रों में 300 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों पर बनी इमारतों में जून तक बरसाती जल के संग्रहण (वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर) का इंतजाम नहीं होने पर उनके नल कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके अलावा उनके स्वीकृत भवन मानचित्र भी रद्द कर दिए जाएंगे। सरकारी इमारतों में भी यह अनिवार्य कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने इस बारे में सभी शहरी निकायों के प्रशासनिक मुखियाओं को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशानुसार भूखंडों पर निर्माण की स्वीकृति देते समय भी जल संग्रहण का प्रावधान करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर नक्शा मंजूर नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने मौजूदा इमारतों में भी यही प्रावधान लागू किया है। ऐसी इमारतों को सूचीबद्ध करने की हिदायत के साथ-साथ सहभागिता योजना से इनका निर्माण पूरा कराने को कहा गया है। इस योजना के तहत सरकारी भवनों के जल संग्रहण ढ़ांचा निर्माण पर होने वाला खर्चा राज्य सरकार वहन करने को तैयार है। *(रा.प. एवं दै.भा., 07.01.06)*

मोबाइल नम्बर नहीं बदलेगा

मोबाइल ग्राहक बिना अपने मोबाइल के नम्बर बदले अपनी मनपंसद मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनी का कनेक्शन ले सकेगा। इसके लिए दूरसंचार नियामक आयोग (ट्राई) ने शिफारिश की है। इस पर अमल होने में करीब एक वर्ष का समय लगेगा। अप्रेल 2007 से इसे लागू किया जा सकेगा।

ट्राई की सिफारिशों के अनुसार नम्बर बदलने की परेशानी दूर होने से उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बेहतर ग्राहक सेवा, नेटवर्क कवरेज तथा गुणवत्ता वाली कम्पनी पुरस्कृत होगी।

ट्राई के अध्यक्ष बैजल के अनुसार दूर संचार दरों में और कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि ट्राई दरों पर नियंत्रण करती है, लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि दरों में कितनी कमी हो सकती है। *(दै.भा., 09.03.06 एवं रा.स्टे. 27.02.06)*

टेलीफोन लाइनें भूमिगत होंगी

मोबाइल कनेक्शन के मामलों में बीएसएनएल ने प्रदेश में पहला स्थान बना लिया है। मोबाइल फोन पर व्यस्त क्षणों में कनेक्टीविटी को बेहतर बनाने के लिए जयपुर में 150 टावर और लगाए जाएंगे तथा 2.10 लाख टेलीफोन लाइनों को भूमिगत किया जाएगा।

निगम के जयपुर जिला दूरसंचार के प्रधान महाप्रबन्धक पी.के. साहा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दिसम्बर 2005 के अंत में 8.70 लाख मोबाइल कनेक्शनों के साथ बीएसएनएल पहले स्थान पर है, जबकि एयरटेल 8.29 लाख कनेक्शनों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा बीएसएनएल ने अपनी क्षमता में भी बढ़ोतरी की है।

अन्य कम्पनियों को भी नेटवर्किंग क्षमता बढ़ानी होगी। बराबर की क्षमता होने से कनेक्टीविटी आसानी से मिलेगी। मोबाइल कंपनियों की हर माह ट्रैफिक मैनेजमेंट समीक्षा होती है और इसकी रिपोर्ट ट्राई को भेजी जाती है।

(दै.भा., 19.01.06 एवं न.नु., 12.3.06)

कम्पनियों की नजर ग्रामीण बाजार पर

बड़े शहरों के साथ कस्बाई व ग्रामीण स्तर पर कारोबारी अतिविधियां बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ टेलीकॉम कम्पनियों को मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि के रूप में मिल रहा है। कम्पनियों ने भी इस स्थिति को समझा है और अपने नेटवर्क में तेजी से सुधार कर रही हैं। टेलीकॉम नियामक संस्था ट्राई के अध्यक्ष प्रदीप बैजल ने भी निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्रामीण स्तर पर सेवाओं का विस्तार करने को कहा है। अतः ऑपरेटरों को ग्रामीण बाजार पर नजर रखनी होगी।

उन्होंने कहा कि कम्पनियों को ग्रामीण स्तर पर निवेश को बड़ी सम्भावना के रूप में लेना चाहिए। मोबाइल कम्पनियां ग्रामीण स्तर पर कम निवेश से बेहतर आय प्राप्त कर सकती हैं। उनके अनुसार टेलीकाम बाजार की संपूर्णता भी तभी हो सकती है जब कम्पनियां ग्रामीण क्षेत्रों तक अपना नेटवर्क स्थापित करें। *(न.नु., 12.02.06 एवं 23.02.06)*

अनचाही कॉल रोकने के होंगे उपाय

अनचाही और निजता में खलल डालने वाली टेलीमार्केटिंग फोन कॉल पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार दो सप्ताह में उपाय खोज लेगी। न्यायाधीश रुमा पाल व दलवीर भण्डारी की पीठ के सामने हर्ष पाठक की जनहित याचिका पर अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने यह आश्वासन दिया।

न्यायालय ने कहा है कि बैंकों द्वारा खाता खुलाने या ऋण का प्रस्ताव व अन्य प्रस्ताव से सेल्यूलर फोन धारक को परेशान किया जाता है। यह बन्द होना चाहिए, अनचाही फोन कॉल बन्द होने से लाखों फोन धारकों को राहत मिलेगी। केन्द्र सरकार ने कहा है इसके लिए न्याय और कानून मंत्रालय, एमटीएनएल और अन्य सेल्यूलर संचालकों और कुछ अन्तरराष्ट्रीय बैंकों से राय मांगी है।

(रा.प., 07.03.06)

ट्राई करेगी बिलिंग सिस्टम की जांच

उपभोक्ताओं की बिलिंग को लेकर बढ़ती शिकायतों को देखते हुए टेलीकॉम नियामक संस्था 'ट्राई' ने सेवा प्रदाता कम्पनियों के बिल तैयार करने के तौर तरीकों की जांच के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों अर्थात ऑडिटर्स की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। मुख्य शिकायतें जैसे बिल की जांच का न होना, स्कीम की कॉल दरों में पारदर्शिता का अभाव होना, पुर्नभुगतान में देरी करना, अधिक बिल जमा हो जाने पर पुर्नभुगतान में देरी करने आदि से सम्बन्धित हैं।

संस्था ने आपरेटरों को भी हिदायत दी है कि वे बिलिंग के तौर-तरीकों और मीटरिंग को आसान बनाएं। संस्था अब कम्पनियों के इन सभी तौर-तरीकों की जांच करेगी और इनकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों से करेगी। किसी तरह के शुल्क या कॉल दर में परिवर्तन या सेवा बन्द करने की भी उपभोक्ताओं को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। *(न.नु., 26.03.06)*

लो कर लो बात एक रुपए में

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के फिक्स फोन और मोबाइल उपभोक्ता देश के किसी भी हिस्से में किसी भी समय किसी भी फोन पर एक रुपए प्रति मिनट की दर से कॉल कर सकेंगे। बहुप्रतीक्षित 'वन इंडिया' योजना की घोषणा ने देश की संचार क्षेत्र में एक नई क्रान्ति ला दी है।

शुरुआती दौर में देशभर में आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल के करीब 16 रुपए प्रतिमिनट लगते थे। वर्ष 2000-01 में मोबाइल कंपनियों ने नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया तब से लगातार प्रतिस्पर्धा चलती जा रही है। दूसरी कंपनियां भी 'वन इंडिया' योजना के अलावा विशेष पैकेज के जरिए ग्राहकों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं।

इस प्रतिस्पर्धा का लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। वे अब चाहे कश्मीर से कन्या कुमारी या चंडीगढ़ से लेकर चेन्नई तक कहीं भी काल करें सिर्फ एक रुपए में बात हो सकेगी। बीएसएनएल के अलावा टाटा, रिलायंस, एयरटेल, रेनबो और हच जैसी कम्पनियां अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और अपना नेटवर्क सुधारने में करोड़ों रुपए का निवेश कर रही हैं।

(रा.प., 24.01.06 एवं दै.भा., 11.02.06)

उपभोक्ता मंच

नोकिया कम्पनी हर्जाना दे

जयपुर निवासी ओम प्रकाश गोयल ने नोकिया कम्पनी का मोबाइल हैण्डसेट एम.आई.रोड़ स्थित ताज रेडियो एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा था। लेकिन कुछ समय बाद हैण्डसेट में तकनीकी खराबी आ गई और उसने काम करना बन्द कर दिया। इस सम्बन्ध में उन्होंने फर्म को अवगत कराया लेकिन हैण्डसेट की खराबी दूर नहीं की गई। उनसे खराबी दूर करने के लिए एक हजार 5 सौ रुपए की मांग भी की गई।

आखिर उन्होंने उपभोक्ता मंच,जयपुर में परिवाद दायर किया और मंच को सम्पूर्ण स्थिति से अवगत कराया। मामले की सुनवाई पर मंच ने नोकिया इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली और फर्म को सेवा का दोषी माना। मंच ने आदेश दिया कि परिवादी को नया हैण्डसेट दिया जाए साथ ही मानसिक संताप और परिवाद व्यय के लिए 5 हजार रुपए संयुक्त या पृथक रूप से अदा करे। *(रा.प., 25.01.06)*

सड़कों के लिए 37 करोड़ रुपए मंजूर

प्रदेश की अंतरराज्यीय महत्व की सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 36 करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर किए हैं। यह जानकारी देते हुए राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ ने बताया कि केन्द्र सरकार को भेजे गए 77 करोड़ रुपए के सड़क विकास संबंधी प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। इनमें से 12 करोड़ 30 लाख रुपए के प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं।

इस राशि में से हनुमानगढ़ जिले में भादरा-झांसल सड़क पर 5 करोड़ 30 लाख, बांसवाड़ा में गढ़ी-बागीदोरा-कुशलगढ़ सड़क पर एक करोड़ 19 लाख, अलवर जिले में रामचन्द्रपुरा सड़क पर एक करोड़ 40 लाख और अलवर-शाहपुरा सड़क पर 67 लाख, सवाई माधोपुर जिले में टोंक-शिवदासपुरा रोड़ पर 5 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च होंगे। *(दै.भा.एवं रा.स्टे, 01.01.06)*

जयपुर शहर में बनेंगे फ्लाइओवर

जयपुर विकास प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी संभावित स्थानों पर फ्लाइओवर और आरओबी बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही शुरू कर दी है। दो साल में शहर का नक्शा पूरी तरह बदला-बदला सा नजर आने लगेगा। इसके तहत शहर में 400 करोड़ रुपए की लागत से 17 फ्लाइओवर और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण कराया जाएगा।

जेडीए इससे पहले एक दर्जन फ्लाइओवर और आरओबी बना कर शहर को पहले ही आधुनिक रूप दे चुका है। इससे शहर में ट्रेफिक दबाव कम करने और यातायात को सुगम बनाने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा शहर की सभी सड़कों की मरम्मत का काम भी जेडीए ने करने का जिम्मा लिया है। इसके लिए जेडीए द्वारा एक समिति बनाई गई है, जो सड़क के खड्डों की शिकायत मिलने पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कर रही है।

(दै.भा., 13.02.06 एवं रा.स्टे., 10.03.06)

केन्द्रीय सड़क मंत्रालय से मिली मदद

सार्वजनिक निर्माण मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने बताया कि केन्द्रीय सड़क निधि योजना के तहत राज्य में 740 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के लिए 84 करोड़ 53 लाख रुपए की स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं।

इस साल केन्द्र सरकार से इस निधि के तहत 121 करोड़ 16 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो चुकी है। उन्होने कहा है कि मार्च, 2006 तक केन्द्र सरकार की ओर से आवंटित राशि खर्च हो जाएगी। सरकार ग्रामीण सड़कों के विकास और गांवों को सड़कों से जोड़ने के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर भी काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को विस्तृत परियोजना भेजी है और 2100 करोड़ रुपए की मांग की है।

योजना आयोग ने प्रदेश की इस योजना की सराहना की है। सरकार मानती है कि प्रदेश के गांवों को तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर 11 वीं योजना के शुरू होने से पहले ही प्रदेश के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना जरूरी है।

(दै.भा., 10.02.06 एवं रा.प.,28.3.06)

छह लेन का होगा जयपुर-दिल्ली रोड़

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत हरियाणा सीमा से जयपुर तक व किशनगढ़ से गुजरात सीमा तक चार लेन के राजमार्ग को छह लेन का बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के इस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री टी.आर.बालू ने अपनी सहमति दे दी है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को जयपुर के लिए नए बाईपास की जरूरत के बारे में भी जानकारी दी और जयपुर-अजमेर रोड़ से टोंक रोड़ होते हुए आगरा रोड़ तक बाइपास बनाने की योजना को राष्ट्रीय परियोजना में प्राथमिकता से शामिल करने पर जोर दिया। बालू ने अगले छह महीने में इस पर केबिनेट की मंजूरी लेने का भी आश्वासन दिया है।

(रा.प. एवं रा.स्टे., 11.01.06)

सड़क सुरक्षा शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अशोक गांगुली का कहना है कि आगामी शैक्षणिक सत्र में सड़क सुरक्षा शिक्षा को बोर्ड पाठ्यक्रम में शामिल करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी।

गांगुली यातायात पुलिस और मुस्कान संस्था की ओर से सड़क सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर क्लार्क्स आमेर होटल में हुई संगोष्ठी में मुख्यवक्ता के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर सत्यप्रिया सिंह, पुलिस अधीक्षक (यातायात)ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। *(रा.प., 26.03.06)*

बनावट में खामी, जिन्दगी पर भारी

आबादी के बीच सड़कों पर तेज गति से दौड़ते वाहन और सुरक्षा नियमों की पालना नहीं करना ही क्या दुर्घटना का कारण है? सड़क दुर्घटनाओं के पीछे लोगों की लापरवाही के साथ-साथ सड़कों की बनावट भी कम जिम्मेदार नहीं होती। जयपुर शहर में पिछले तीन सालों में सड़क दुर्घटना के सबसे ज्यादा मामले अजमेर रोड के 200 फीट बाईपास पर हुए।

दूसरा स्थान झोटवाड़ा रोड और गोपालपुरा बाइपास का है। दिल्ली रोड पर बन्द की घाटी दुर्घटनाओं को आए दिन निमंत्रण देती है। सब जगह दुर्घटना के कारण अलग-अलग हैं। भारी ट्रेफिक, रोडकट्स, खतरनाक मोड़, सड़क के गड्ढे और लापरवाही आदि सभी दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। राजस्थान पुलिस ने पूरे राज्य की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं का अध्ययन करके राष्ट्रीय और राजमार्गो पर 250 स्थान चिन्हित किए थे, जहां तीन साल के भीतर दो से लेकर 163 दुर्घटनाएं हुई थीं।

इन स्थानों की तकनीकी खामी दूर करने के लिए रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजी गई थीं । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एस.आर.तुनगरिया का कहना है कि कुछ स्थानों को ठीक करा दिया गया है, जहां ज्यादा काम है वहां के लिए एस्टीमेट मंत्रालय को भेजा गया है। *(रा.प., 02.01.06 एवं दै.भा., 11.03.06)*

सवारी की जान सांसत में

राजधानी में तीन सौ से अधिक जीपें विभिन्न राजमार्गो पर अवैध रूप से चल रही हैं। जीपों में सवारियां भी रोड़वेज बस स्टैण्डों के नजदीक से भरी जा रही हैं। जीप आगे तब ही बढ़ती है जब उसमें दो-चार सवारियां बाहर लटकने की नौबत आ जाती है। खास बात यह है कि अवैध जीपों का संचालन भी परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि अवैध रूप से चलने वाली जापों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद विभाग के अधिकारियों व इंस्पेक्टर की मिलीभगत से राजधानी से गुजरने वाले हर राजमार्ग व आस-पास के कस्बों के लिए जीपें चल रही हैं। क्षमता से अधिक सवारियां भरने के बाद इनकी रफ्तार भी हवा में उड़ने के बराबर होती है। ऐसे में सवारियों की जान हमेशा खतरे में रहती है। जीपों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बड़ी संख्या में लोग जान से हाथ धो चुके हैं, लेकिन पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी आमजन को खतरे में डालकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

(रा.प., 25.02.06)

जनवरी में प्रथम सप्ताह सड़क सुरक्षा के नाम

जनवरी माह का प्रथम सप्ताह सड़क सुरक्षा के नाम रहा। दो से आठ जनवरी तक जयपुर में यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और गैर सरकारी संगठनों की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्कूलों, कच्ची बस्तियों और अनेक सार्वजनिक स्थानों पर यातायात जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए गए।

आरटीओ कार्यालय में वाहन चालक प्रशिक्षण कैम्प और यादगार में प्रशिक्षण कक्ष का उद्घाटन भी हुआ। स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली निकाली और लोकगीतों व नाटकों के माध्यम से वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। अनेक कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। रोड शो, वीडियो फिल्म प्रदर्शन आयोजित किए गए। वाहन चालकों को हेलमेट व सीट बैल्ट लगाने के साथ-साथ वाहन चलाने के नियमों की पालना करने की सीख दी गई।

ऐसे अनेक कार्यक्रमों के पीछे एक ही उद्देश्य था कि किसी प्रकार खूनी सड़कों पर दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। लेकिन क्या वाहन चालकों ने इससे कुछ सीख ली? सत्यप्रिया सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात का कहना है कि दुर्घटनाओं को रोकने में सरकारी मशीनरी से ज्यादा अहम भूमिका आम आदमी की है।

(दै.भा., 01.01.06 एवं रा.प., 03.01.06)

तमाशबीन नहीं मददगार बनें

पूरे देश की सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें समय से चिकित्सकीय सुविधा न मिलने की वजह से होती हैं। अगर कहीं दुर्घटना हो जाए तो आप तमाशबीन की भूमिका में न खड़े हों। उस वक्त आपकी भूमिका मददगार की होनी चाहिए।

शीघ्रता में पहुँचाई गई आपकी मदद न केवल एक जीवन बचाती है, बल्कि एक पूरे परिवार का भविष्य संभालती है। किसी का जीवन बचाने से बढ़कर शायद ही कोई दूसरा पुण्य हो। पता नहीं क्यों लोग इतनी सहजता से मिलने वाला पुण्य कमाने से चूक जाते हैं। - सत्यप्रिया सिंह, अधीक्षक (यातायात)

(रा.प. 08.01.06)

ट्रेफिक प्लान सुधार पर पूरी नजर

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था से खफा मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे खुद ट्रैफिक सुधार कार्यक्रम में रुचि ले रही हैं। हाल ही 'जाग' की बैठक में अगले बीस साल को ध्यान में रख कर ट्रैफिक प्लान बनाने का निर्णय काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके तहत एरिया ट्रैफिक नियन्त्रण सिस्टम व रेडलाइट स्पीड केमरे भी लगाए जाएंगे। बैठक में तय किया गया है कि इस कार्य के लिए ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड मेनेजमेन्ट एजेंसी का काम करेगा और जयपुर विकास प्राधिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराएगा।

प्राधिकरण ने ट्रैफिक प्लान बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इन सब कामों पर मुख्यमंत्री कार्यालय सीधी निगरानी रखेगा और हर माह इसकी समीक्षा होगी। अब तक यातायात पुलिस को हर साल 20-25 लाख रुपए देकर इतिश्री करने वाला प्राधिकरण अब हर साल 4-5 करोड़ रुपए खर्च कर शहर की ट्रैफिक कन्ट्रोल व्यवस्था को 'हाई-फाई' करेगा। ट्रैफिक कन्ट्रोल बोर्ड ने भी पुणे की तर्ज पर शहर में स्वचालित ट्रैफिक नियन्त्रण व्यवस्था लागू करने की तैयारी प्रारम्भ कर दी है।

(रा.प.एवं दै.भा., 09.01.06 एवं दे.भा., 07.03.06)

क्या-क्या होने वाला है

- चौराहों पर एटीसी (ऑटोमेटिक ट्रेफिक कन्ट्रोल) व्यवस्था
- हर चौराहे पर लगने वाले सेंसर से दबाव के अनुसार यातायात का नियंत्रण
- चौराहों पर कैमरे लगेंगे
- लालबत्ती व जैबरा लाइन का उल्लंघन करने पर नम्बर प्लेट, वाहन के रंग व स्टॉप लाइन से दूरी के फोटो खींचे जाएंगे। ऐसे वाहन मालिकों को जुर्माने के लिए नोटिस भेजे जाएंगे।
- जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक (उत्तर) को चारदिवारी में एक-एक दिन बाजार बन्द रखने की व्यवस्था। व्यापारियों से बात करने के बाद एक बाजार बन्द और पास के बाजार खुलने की व्यवस्था होगी जिससे बन्द बाजार में पार्किंग हो सके।
- संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेकर रंगमंच पर पार्किंग
- व्यावसायिक परिसरों में अवैध रूप से पार्किंग स्थलों में निर्माण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई। प्रथम चरण में 10 परिसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

जेडीए करेगा ग्रामीण सड़कों का निर्माण

जयपुर विकास प्राधिकरण गांवों की सड़कों के निर्माण व विकास पर 12 करोड़ 81 लाख रुपए खर्च करेगा। प्राधिकरण प्रवक्ता के अनुसार जोन 11 में 47.80 किलोमीटर की 23 ग्रामीण सड़कों पर अब तक 2 करोड़ 98 लाख 26 हजार रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

मार्च तक करीब 3 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए और खर्च किए जाएंगे। इन सड़कों में बालावाला से तेजावाला, ग्राम पोस्ट लखाना, मुहाना से तेजाजी मंदिर से रातलिया मार्ग, वाटिका से चंदलाई, श्रीरामपुरा से लखाना रोड़, मुकुंदपुरा बिंदायका रोड़ से महाराजपुरा तक की विभिन्न सड़कों पर कुल 6 करोड़ 43 लाख 38 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। *(रा.प.एवं दै.भा., 12.01.06)*

गाड़ी में जाने क्या नया है

शहर में तीन सौ वाहनों की रोजाना खरीद हो रही है। बिकवाली की रफ्तार का पैमाना यहीं रहा तो दस बरस बाद जयपुर शहर में ही दुपहिया वाहन और चौपहिया वाहन की संख्या दस लाख का आंकड़ा छू जाएगी। वैसे बीस सालों में दुपहिया वाहनों की खरीद सात गुनी और चौपहिया वाहनों की बिक्री आठ गुनी से भी अधिक पहुंच चुकी है।

शहर की सड़कों पर दौड़ते वाहनों की संख्या दिन-प्रतिदन बढ़ती जा रही है। पेट्रोल-डीजल की निरंतर बढ़ती दरें भी लोगों को नए वाहन खरीदने से नहीं रोक पाई। जहां वर्ष 1985 में एक दिन में औसतन चालीस वाहन सड़क पर आते थे, वहीं यह आंकड़ा लगभग दो दशक बाद 297 तक जा पहुंचा है। *(रा.प. 27.02.06)*

'सड़क सुरक्षा सप्ताह' में कट्स की भागीदारी

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 2 से 8 जनवरी, 2006 को 'सड़क सुरक्षा सप्ताह' का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के साथ 'कट्स' ने भी अपनी भागीदारी इसमें दी।

सप्ताह के प्रारम्भ में 'कट्स' द्वारा सम्पूर्ण राजस्थान में सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के ऊपर एक सर्वे किया गया, जिसकी रिपोर्ट जयपुर के करीब सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई। 'कट्स' ने उद्घाटन समारोह में भाग लेने के अतिरिक्त मोटर यान अधिनियम की धारा 134 पर विशेष अभियान चलाकर आम नागरिक, चिकित्सकों व यातायात कर्मियों को जागरूक करने का प्रयास किया।

इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख चौराहों पर 'सड़क सुरक्षा' शिविरों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं की जानकारी प्रदान की गई।

विविध सेवाएं

छपी कीमत पर मिलेंगी दवाइयां

केन्द्र सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे देश में दवाएं छपी कीमत पर मिलेंगी। इसके रेपर पर सभी टैक्स जुड़कर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनका नाम, उनके निर्माण की तिथि, अवधि समाप्त होने की तिथि और कीमत छपी होगी।

यह निर्णय सरकार एक अप्रेल, 2006 से लागू करने की तैयारी में है। केन्द्र सरकार की उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए इस निर्णय से पूरे देश में दवाएं समान दर पर मिल सकेंगी। दवा के अलावा बाजार में बिकने वाला हर सामान पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के तहत एमआरपी दर पर ही बिकता है।

अभी दवाओं पर स्थानीय कर अलग से वसूला जाता है। इससे दवा विक्रेता की मनमानी पर रोक लग सकेगी। मनमाने पैसे वसूलने पर ग्राहकों की दवा विक्रेता से कई बार झिक-झिक भी देखी जाती रही है। इस फैसले के लागू होने पर दवा उपभोक्ताओं और दवा विक्रेता दोनों को संतुष्टि मिल सकेगी।

(रा.प., 03.01.06 एवं दै.भा., 12.02.06)

ग्रामीण डाकघरों की हालत सुधरेगी

राजस्थान सहित कई प्रदेशों में ग्रामीण डाक सेवा की बुरी हालत है। इसमें सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने संचार सेवा को मजबूत बनाने का फैसला किया है। संचार मंत्रालय गरीबों की इस सस्ती और सब्सिडी पर चलने वाली सरकारी सेवा को सुदृढ़ करेगा। इसके लिए संबधित कानूनों में बदलाव भी किया जा रहा है।

डाकघरों के आधारभूत ढ़ांचे को भी नई तकनीक और सेवाओं को जोड़कर मजबूत किया जा रहा है। कूरियर कंपनियों पर नियंत्रण के लिए कानूनों में संशोधन किया जाएगा। आशा है कि इसी बजट सत्र में 150 साल पुराने डाक एवं तार कानूनों में संशोधन कर उन्हें लागू किया जा सकेगा।

(दै.भा. एवं रा.स्टे., 15.02.06)

स्कूलों के गोपनीय निरीक्षण ने खोली पोल

राज्य के शिक्षा विभाग ने वास्तविक हालात जानने के लिए वृहत स्तर पर स्कूलों का गोपनीय निरीक्षण कराया। इस निरीक्षण ने शिक्षा विभाग की आंखें खोल दी हैं। गांवों में लगभग आधे शिक्षक नियुक्ति स्थल पर नहीं ठहरते। कहीं हाजरी ज्यादा है और बच्चे कम हैं, तो कहीं शिक्षक हाजरी लगाकर स्कूल के काम का बहाना बना नदारद हो जाते हैं।

स्कूलों में शिक्षकों और फर्नीचर की कमी भी सामने आई। यह भी सामने आया कि छात्र मिड-डे-मील लेने के बाद स्कूल से गायब हो जाते हैं। करीब एक हजार स्कूलों में हुए इस निरीक्षण ने ऐसी व्यवस्थाओं की कई कमियों को उजागर किया है।

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा के प्रमुख सचिव सी.के. मैथ्यू ने व्यवस्था की इस कमी को गंभीर माना है और कहा है कि हर माह इस तरह के गोपनीय निरीक्षण कराए जाएंगे और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। *(दै.भा., 16.02.06)*

'जाग' की तर्ज पर होगा विकास

जयपुर एजेंडा एक्शन ग्रुप 'जाग' की तर्ज पर राज्य के सात और शहरों का विकास किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए स्वायत शासन राज्य मंत्री प्रतापसिंह सिंघवी ने बताया कि इसके लिए अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा शहरों का चयन किया गया है।

उन्होंने कहा कि जाग के तहत जयपुर में शहरी जन सहभागिता, पेयजल, ठोस कचरा प्रबन्धन, यातायात प्रबन्धन, विरासत संरक्षण, क्राफ्ट विलेज, निजी सहभागिता व सुशासन को जोड़ कर किए गए काम काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। इससे प्राप्त परिणामों और कामों के मद्देनजर ही इन शहरों का चयन किया गया है ताकि जन सेवाओं का द्रुत गति से विकास हो और आम आदमी आधारभूत सुविधाओं के विकास से लाभान्वित हो सके।

(रा.प. एवं दै.भा., 02.02.06)

सरकारी सेवाओं का लाभ जनता को मिले

विश्व बैंक ने हाल ही जारी रिपोर्ट में बताया है कि राजस्थान में सरकारी सुविधाओं से जनता को मिले लाभ का स्तर काफी कमजोर है। इससे मानव विकास की गति आगे नहीं बढ़ पा रही। पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सेवा, राशन की दुकान, परिवहन व शिक्षा के मामले में नागरिकों की संतुष्टि को आधार मान कर तैयार रिपोर्ट में प्रदेश की निगरानी प्रणाली को कमजोर बताया गया है।

राज्य सरकार व विभिन्न लाभार्थी वर्गों से चर्चा के बाद बनी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो साल से राज्य में सुधार की गति अच्छी बनी है, लेकिन इसमें और तेजी लाई जाकर वृद्धि दर को 7-8 प्रतिशत तक लाना जरूरी है। इसके लिए कृषि क्षेत्र को चार प्रतिशत की वृद्धि पर कायम रखने और गैर कृषि क्षेत्र में वृद्धि को 8-9 प्रतिशत तक लाये जाने की जरूरत बताई गई है।

(रा.प., 31.03.06)

चिकित्सा सुविधाओं में असमानता क्यों?

उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत ने गांवों और नगरों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में असमानता पर गहरी चिन्ता जताई है। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों को सीमित मात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, जबकि समृद्ध वर्ग के लोगों के लिए उत्कृष्ट सेवाएं हैं।

उन्होंने कहा कि आज इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 26 प्रतिशत लोगों सहित सभी नागरिकों को पर्याप्त एवं प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। विश्वसनीय और कम से कम खर्च में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तथा योग सहित सभी चिकित्सा प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत बताई है। *(रा.प., 19.03.06)*

पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

अंक-1, 2006

इस अंक में पढ़िये...

- गरीबों के राशन पर सरकार की घात? 3
- कैदियों का गेहूं - खा गए कौन? 4
- लोकायुक्त का पद खाली 5
- 'चक्रव्यूह' दोषी सांसदों को फटकार 6
- कट्स ने चलाया पोस्टकार्ड अभियान 7

स्त्रोतः रा.प. : राजस्थान पत्रिका, दै.भा. : दैनिक भास्कर, न.नु. : नफा नुकसान, रा.स्टे.: राजस्थान स्टेटमेंट, हि.टा.: हिन्दुस्तान टाईम्स

आधार (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-222, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.5133259, 2282821 फैक्सः 5104258, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org, के लिए केबीएस प्रिंटर्स, जयपुर द्वारा मुद्रित।